उद्यमियों को चाहिए और रियायतें, बदलेंगी नीतियां

निवेश करार करने वाले उद्यमी मांग रहे सस्ती दर पर जमीन, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति भी ज्यादा चाह रहे उद्यमी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में निवेश करार करने वाले उद्यमियों ने सेक्टरवार नीतियों से अधिक रियायतें मांगी हैं। निवेशकों की कुछ जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकार अब नीतियों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन का पहला भूमि पूजन समारोह दशहरा के आसपास होना प्रस्तावित है। सरकार ने इसमें सात लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इनवेस्ट यूपी और औद्योगिक विकास विभाग अदाणी सहित बड़े उद्योगपतियों से संपर्क कर उनके प्लांट शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अदाणी समूह सहित अन्य औद्योगिक समूहों ने सरकार से रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। उनका मानना है कि विकास प्राधिकरण की जमीन की कीमत अधिक होने से उनका अधिकांश निवेश जमीन में चला जाता है। लिहाजा सरकार सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराए।

उद्यमियों ने सुझाव दिया है कि गुजरात व अन्य राज्य एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति कुल निवेश लागत का 125 फीसदी तक कर रहे हैं। जबकि यूपी में शत प्रतिशत तक ही की जा रही है। उन्होंने सरकार से एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति अन्य राज्यों के समकक्ष करने का प्रस्ताव दिया है। उद्यमियों ने एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के साथ निवेश लागत पर सब्सिडी भी देने की मांग रखी है। जबकि सरकार की नीति के तहत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति या सब्सिडी दोनों में से एक ही आर्थिक सहायता मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब औद्योगिक निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति और वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति में कुछ संशोधन करने जा रही है। इसके लिए विभाग में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। जल्द ही नीति में संशोधन का कैबिनेट प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

ब्रिटेन के निवेशकों को प्रदेश में मिलेगी हर संभव मदद

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने ब्रिटेन के निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार निवेशकों को हर संभव मदद करेगी। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट के नेतृत्व में ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की।

ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से की मुलाकात। -विज्ञप्ति

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सकारात्मक माहौल है। कारोबारी सुगमता में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आकर्षक सेक्टोरल नीतियां बनाई हैं। प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था, रोड कनेक्टीविटी, एयर कनेक्टीविटी के साथ निवेशक फ्रेंडली माहौल है। मुख्य सचिव ने अक्तूबर में प्रस्तावित पहले भूमि पूजन ब्रिटेन के सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित भी किया। क्रिस्टीना स्कॉट ने भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का आश्वासन दिया। उधर, डीजीपी मुख्यालय में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशिक्षण, यातायात प्रबंधन और संगठित अपराधों पर नियंत्रण के अपने अनुभवों को साझा किया। डीजीपी आरके विश्वकर्मा की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था की सराहना भी की। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में पुलिस के कार्यों में आधुनिक एवं उच्च तकनीकों का प्रयोग, महिलाओं की सुरक्षा व साइबर अपराध की रोकथाम समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ब्रिटिश उच्चायोग के सदस्य रिचर्ड बारलो, नतालिया लेह के अलावा भावना विज, विभोर सिंह आदि मौजूद थे। इस दौरान डीजीपी मुख्यालय में तैनात वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।